

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड चमोली के द्वारा संचालित क्रियान्वित योजनाओं का विवरण

(राजीव भट्ट)
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
चमोली
फोन न०- 01372252286
मोबाईल न०-7534915323
ई०मेल- ukvibchamoli99@gmail.com

व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना

राज्य सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना का संचालन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता से कार्य/संसाधन क्षमता के आधार पर उद्योग स्थापित किये जाने के उद्देश्य से धनराशि ₹0 5.00 लाख तक की परियोजना लागत को बैंक के माध्यम से वित्त पोषित कराने में सहयोग किया जाता है। योजनान्तर्गत उद्यमी को परियोजना के बैंक वित्त पर ब्याज का 4 प्रतिशत भुगतान वहन करना होता है एवं अन्तर बैंक वित्त ब्याज की अधिकतम 10 प्रतिशत तक धनराशि विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -

1. आयु 18 से 45 वर्ष।
2. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी।
3. शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो अथवा
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पॉलिटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी अथवा
5. स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएँ अथवा
6. यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
7. परियोजना की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना।
8. परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खापी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -

1. पासपोर्ट फोटो।
2. स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
3. फोटो पहचान पत्र।
4. पता पहचान पत्र।
5. जाति प्रमाण पत्र।
6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
7. ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (निर्धारित प्रारूप पर)
8. बैंक शाखा का सहमति पत्र।
9. शैक्षिक/प्राविधिक प्रमाण पत्र।
10. ₹0 20/- के गैर-न्यायिक टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
11. परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खापी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया - ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी रूचि एवं कौशल पात्रता के आधार पर परियोजना अन्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जिले के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

लाभार्थी का चयन - जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर गठित टास्क फोर्स समिति के सम्मुख निरीक्षण रिपोर्ट/आवेदन/अभिलेख पत्र प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा/चयन कार्यवाही कर पात्र पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जाता है। बैंक शाखा द्वारा आवश्यक बैंक वित्त अभिलेखों की औपचारिकताएँ/स्थलीय निरीक्षण पूर्ण कर परियोजना के सापेक्ष ऋण स्वीकृत किया जाता है।

जनपदवार अधिकारियों का विवरण एवम्सम्पर्क निम्नानुसार है -

क्र०म०	जनपद का नाम	दूरभाष सङ्ख्या
1	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली	01372-252286 Mo- 7534915323

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध करवाने तथा विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने क्रेडिट लिंकड योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किया गया। वंचित वर्ग के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्पादन सैक्टर हेतु अधिकतम 25 लाख तक एवं व्यापार/सेवा सैक्टर के लिए अधिकतम 10 लाख तक बैंक वित्त का प्राविधान तथा ₹0 10 लाख से अधिक के उत्पादन सैक्टर तथा ₹0 5 लाख से अधिक की व्यापार/सेवा सैक्टर के लाभार्थियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मार्जिन मनी 35 प्रतिशत कुल परियोजना लागत का अनुदान का प्राविधान है। अब लाभार्थी pmegp e portal पर जा कर अपने आवेदन पत्र को स्वयंम ऑनलाईन कर सकते हैं।

पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -

1. आयु 18 से 45 वर्ष।
2. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी।
3. शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो अथवा
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पॉलिटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी अथवा
5. स्वतः रोजगार में रुचि रखने वाली महिलाएँ अथवा
6. यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
7. परियोजना की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना।
8. परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खापी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -

1. पासपोर्ट फोटो।
2. आधार कार्ड
3. जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
5. ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (निर्धारित प्रारूप पर)
6. बैंक शाखा का सहमति पत्र।
7. शैक्षिक/प्राविधिक प्रमाण पत्र।

आवेदन की प्रक्रिया - ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी रुचि एवं कौशल पात्रता के आधार पर परियोजना अन्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जिले के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

लाभार्थी का चयन - जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त/क्लेक्टर की अध् यक्षता में गठित जिला कार्यपाल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा/चयन कार्यवाही कर पात्र पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जाता है।

जनपदवार अधिकारियों का विवरण एवम्सम्पर्क निम्नानुसार है -

क्र०म०	जनपद का नाम	दूरभाष सङ्ख्या
11	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली	01372-252286 Mo- 7534915323

उत्तराखण्ड ऊन योजना

उत्तराखण्ड राज्य में ऊनी व्यवसाय की असीम संभावनाओं दृष्टिगत उत्तराखण्ड खापी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जिले में 04 उत्पादन केन्द्र के माध्यम से खापी के अन्तर्गत ऊन की कटाई व बुनाई का कार्य किया जाता है। जिससे कि उत्तराखण्ड में रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें।

ऊन बैंक की स्थापना

उत्तराखण्ड में भेड पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खापी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नहीं थी, जिससे भेड पालकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड खापी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गई है। योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थानीय भेडपालकों की ऊन को विभागीय ऊन क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाता है। वर्ष 2015-16 में ऊन का अधिकतम मूल्य ₹0 106.00 प्रति किलो ग्राम कर पिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय प्रशोधित ऊन बिक्री हेतु उपलब्ध रखा जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया - उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय ऊन क्रय हेतु क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अथवा विभागीय उत्पादन केन्द्रों में आवेदन कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। कार्यालय/केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है-

जनपद	उत्पादन केन्द्र	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	दूरभाष सङ्ख्या
चमोली	गोपेश्वर, भीमतल्ला, ढेवाल, रडुवा	श्रीनगर	01346-25711

खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट

प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर गाँधी जयन्ती के शुभ अवसर पर खापी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट का प्राविधान किया जाता है। छूट की अवधि 108 कार्यकारी दिवसों के लिये उपलब्ध कराई जाती है। खापी वस्त्रों की बिक्री छूट के अन्तर्गत जिले की 02 खापी संस्थायें एवं 13 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आम जनमास को खापी, पौली, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की खरीद पर नियमानुसार छूट की सुविधा दी जाती है। खापी वस्त्रों पर छूट की व्यवस्था से खापी वस्त्रों को बाजार प्रतिस्पर्धा में लाने के कारण उत्पादन बढ़ता है, जिससे कतकर व बुनकरों की मासिक आय में वृद्धि होती है।

उत्तराखण्ड वनस्पति रेशा बैंक

उत्तराखण्ड खापी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा स्थानीय कच्चे माल के बेहतर उपयोग एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध डास कंडाली, भीमल एवं रामबांस का रेशा के उपयोग एवं उसके संग्रहण से रोजगार की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड खापी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2009-10 में रेशा बैंक की स्थापना भी की गयी।

क्र0म0	रेशे का विवरण	वर्तमान समर्थन मूल्य (₹0में)
1	डास कंडाली	45-00
2	भीमल	10-00
3	रामबांस	50-00

स्थानीय स्तर पर रेशा आधारित क्राफ्ट को विकसित करने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों का जो रेशा संग्रह कार्य में लगे हैं, रोजगार से जोडा जा सकेगा। उपरोक्त प्राकृतिक वनस्पति रेशा का क्रय निम्नानुसार जनपदों के केन्द्रों पर किया जायेगा।

क्र0म0	जनपद	क्रय केन्द्र	क्रय स्थान	अधिकृत कार्यालय	दूरभाष सङ्ख्या
6	चमोली	मुन्डोली, एथला, सितेल, जोषीमठ, उरगम।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) उत्तराखण्ड खापी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्रीनगर गढवाल	01346-257118

प्रदर्शनी

उत्तराखण्ड खापी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में पंजीकृत व वित्त पोषित उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों के उत्पादों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बिक्री के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं जनपद स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन निम्नानुसार किया जाता है।

क्र०म०	स्तर	स्थान	अवधि	न्यूनतम स्टाल क्षमता
2	जनपद	चमोली	माह-अक्टूबर, 07 िन	25

उद्यमियों को प्रदर्शनी में प्रतिभाग हेतु स्वयं खर्चा वहन करना होगा। प्रतिभागी के अनुरोध पर प्रदर्शनी अवधि में रात्रि ठहरने की व्यवस्था विभाग द्वारा कराई जा सकती है जिसका भुगतान प्रतिभागी को स्वयं वहन करना होगा। स्टाल किराया खापी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित दरों पर प्राप्त किया जाता है। खापी इकाई हेतु साईज 3 X 3 वर्गमीटर एवं ग्रामोद्योगी इकाई हेतु 3 X 2 वर्गमीटर क्षेत्रफल का स्टाल उपलब्ध कराया जाता है। स्टाल में निर्धारित मानकों के अनुसार मेज, कुर्सी, विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध रहती है।

पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -

1. भारतवर्ष में खापी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा खापी ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत/वित्त पोषित इकाई/संस्था/समिति/व्यक्तिगत उद्यमी एवं विभागीय इकाईयाँ।
2. खापी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन कार्य कर रही इकाई/संस्था/समिति/व्यक्तिगत उद्यमी,
3. खापी एवं ग्रामोद्योग के सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही इकाई/संस्था/समिति/व्यक्तिगत उद्यमी,
4. पीएमईजीपी योजना अन्तर्गत वित्त पोषित इकाईयाँ,
5. बांस, प्राकृतिक रेशा, इकाई/समूह (बांस एवं रेशा विकास बोर्ड अथवा सम्बन्धित सरकारी विभाग की संस्तुति पर)
6. उत्तराखण्ड राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह (सम्बन्धित सरकारी विभाग की संस्तुति पर)

स्टाल किराया -

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -

1. पासपोर्ट फोटो।
2. खापी प्रमाण पत्र (खापी संस्था/समिति हेतु)।
3. अस्थाई/स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र (ग्रामोद्योग इकाई/उद्यमी हेतु)।
4. सरकारी विभाग का संस्तुति पत्र (हथकरदया, बांस, रेशा एवं उत्तराखण्ड राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह हेतु)

आवेदन की प्रक्रिया - इच्छुक प्रतिभागी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जनपद के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं अथवा सीधे मुख्यालय उत्तराखण्ड खापी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ढहरापून में जमा कर सकते हैं।

लाभार्थी का चयन - प्रदर्शनी स्टाल आवंटन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

योजना का आवेदन का प्रारूप डाउनलोड आप्शन में उपलब्ध है।

खादी सङ्गथाओङ्गो सहयोग योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में खापी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा प्रमाणित खापी की संस्थाओं को, जो आर्थिक एवं संस्थागत रूप से कमजोर हैं तथा अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रही हैं, ऐसी संस्थाओं के उत्थान हेतु उनके उत्पादन केन्द्रों के सुदृढीकरण तकनीकी विकास, डिजायन विकास में सहायता प्रिया जाना है। योजना का प्रारम्भ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या-934(1)/VII-2-16/210-एम0एस0एम0ई0/2015 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा किया गया है।

पात्रता

योजनान्तर्गत खापी और ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा प्रमाणित खापी संस्थायें जो निर्धारित मानको के अन्तर्गत अच्छापित हों किन्तु परिस्थिति के कारण अपने उत्पादन कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रही हों अथवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बन्गी के कगार पर हों, ऐसी विषम परिस्थिति जिसके कारण संस्था से जुड़े कर्तकरों/बुनकरों को रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है, उन्हें उक्त योजना का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा। यह भी आवश्यक हो कि संस्था द्वारा खापी से निर्मित हाथ कता, हाथ बुना वस्त्र खापी मानक के अनुरूप तैयार किया जा रहा हो। संस्था के वर्तमान के उत्पादन कार्य में धनराशि की वास्तविक आवश्यकता तथा सहायता हेतु सम्भवित अन्य कोई स्रोत न होना।

चयन की प्रक्रिया -

संस्था का चयन गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।